बिहार में पृथकरण आंदोलन

मो0 सनाउल्लाह

बंगाल से बिहार के पृथ्थकरण हेतु चलाए जाने वाले वैचारिक संघर्ष के प्रथम चरण में, बंगाल की अखंडता तथा बिहार बंगाल पृथ्थकरण के समर्थकों ने अपने–अपने पक्ष में दलीलें दी, और सरकार के समक्ष अपने पक्ष को रखा। ब्रिटिश सरकार इस नवोदित विवाद को न सुलझाना चाहती थी और न ही समाप्त होने देना चाहती थी। मामले को उलझाए रखने के लिए, उसने टाल–मटोल की नीति अपनाई, ताकि समय के साथ–साथ बंगाल में स्वतः दो परस्पर विरोधी वैचारिक मंच बन जाए और किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी भावना का उदय न हो। सरकार की यह नीति सफल रही। इसी बीच बंगाल के गवर्नर सर ऐश्ले ईडन ने एक परिपत्र जारी कर, बिहार के अन्तर्गत कतिपय सरकारी सेवाओं को केवल बिहारियों के लिए आरक्षित कर दिया। बंगाल से प्रकाशित पत्रों ने ईडन के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। 17 जनवरी 1881 के सहचर में परिपत्र के नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करते हुए कहा गया कि उक्त सरकारी आदेश का उद्देश्य बिहार में बंगालियों की नौकरियों पर प्रतिबंध लगाना है।